श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि चूंकि दिल्ली से किसी दूसरे देश की सीमा नहीं मिलती इसलिए यहां से तस्करी में माल बाहर भेजने का प्रश्न नहीं उठता और फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिल्ली से पंजाब को काफी मात्रा में यह वनस्पति घी चोरबाजारी में जाता है, तो पंजाब की सीमा दूसरे देश से मिली हुई है और इस तरह से पंजाब से वह घी वहां भेजा जाता है, इसकी खबर सरकार को है ?

Shri Shinde: We have not received any complaint to that effect.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनावों के लिए सरकारी शासन-तन्त्र का प्रयोग

+

*182. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के गत चुनावों में सरकारी शासन-तन्त्र (मशीनरी) का प्रयोग किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) Some allegations were received by the Election Commission about the use of Government machinery in connection with the last biennial elections to the Uttar Pradesh Legislative Council. Some of them were too vague for any action and some were reported baseless. Some cases have been referred to the Chief Electoral Officer and Chief Secretary of the State to find out whether these allegations have any basis in facts. Their reports are awaited by the Election Commission.

(b) Does not arise.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कुछ शिकायतें हमें मिली हैं, यह सही है, तो वह कौन कौन सी शिकायतें हैं जो चुनाव के अधिकारियों को मिली हैं ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: I have got a long list here. There is reference to use of government vehicles and all that. The entire list is here. But as I said, this is being inquired into and we are awaiting the Election Commission's report.

श्री हुकम चन्द कछवाय : श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इस चुनाव के अन्दर जो सुरक्षा कोष का पैसा एकत्रित किया गया उस पैसे का कुछ मिनिस्टर लोगों द्वारा उपयोग किया गया।

Shri C. R. Pattabhi Raman: To the best of my knowledge, that is not the charge.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें विधि मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनाव में सरकारी तन्त्र के प्रयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं क्या अधिकांश शिकायतें इनमें से वह हैं कि जो मिनिस्टर यह चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने सरकारी गाड़ियों का और सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो उनके संबंध में निष्पक्ष जांच करने के लिए कौनसा तंत्र आप इस्तेमाल करेंगे कि जिस से वास्तविकता का पता लग सके ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : इसकी जांच का हक कमीशन को है और कमीशन ने जिन बातों को समझा कि उसकी जांच जरूरी है उसको गवर्नमेंट के पास भेजा है और चीफ एलेक्टोरल आफिसर के पास भी भेजा है। जब उनकी रिपोर्ट कमीशन के पास

आयेगी तब कमीशन को मालूम होगा कि शिकायतें की गई हैं वह सही हैं या नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मिनिस्टर के खिलाफ शिकायतें हैं. . .

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : अगर आप यह चाहते हों कि क्या क्या शिकायतें हैं तो उसकी फेहरिस्त मैं आपको दे सकता हूं

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं चूंकि उन एलेक्शनों में यह बात हुई जिनमें मिनिस्टर उम्मीदवार थे तो जब मिनिस्टर उम्मीदवार थे तो उनकी तहकीकात भी अगर गवर्नमेंट को ही करना है तो सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी एलेक्शन कमीशन की है । एलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट गवर्नमेंट से ही नहीं मांगी है, बल्कि एलेक्टोरल आफिसर से भी मांगी है और उनकी रिपोर्ट के आने पर फिर एलेक्शन कमीशन को अख्तियार होगा कि यह कोई और तरीका अख्तियार करना चाहें तो कर लें. . . (**व्यवधान**) . . .

Shri Dinen Bhattacharya: He is also an officer of the UP Government.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप ने भी विधि मन्त्री से पूछा कि क्या कुछ शिकायत मिनिस्टरों के खिलाफ हैं लेकिन. . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया कि इंडिपेंडेंट मशीनरी एलेक्शन कमीशन है । उन्होंने एलेक्टोरेल आफिसर से भी रिपोर्ट मांगी है उससे भी यह तहकीकात करा रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि मिनिस्टरों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं क्या ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने तो यह जवाब दिया कि जो शिकायतें हैं उनमें मिनिस्टरों के नाम भी हैं और मैं सारी शिकायतों की फेहरिस्त आपके सामने दे सकता हूं ।

Shri D. C. Sharma: Is it not a fact that some of the members of the Legislative Assembly in UP, mostly the Opposition Members, have sold their votes at black market rates. . . .

Mr. Speaker: Order, order. I would not allow that question.

Shri D. C. Sharma: May I know what has been done in that connection?

Shri Surendranath Dwivedy: He means to say that the Congress Members are selling at the market rate; at the blackmarket rate the opposition only is selling.

Mr. Speaker: We ought to behave with greater responsibility. If all of us are thieves, there is no use of publicising it.

Shri Bhagwat Jha Azad: It is just a retort to the hon. Members to behave responsibly. I think this should be directed to them.

Mr. Speaker: This is directed to every Member, whoever he might be, and wherever he might be.

Shri Surendranath Dwivedy: It is not only in U.P. Is it not a fact that often the Government machinery is used for the purpose of elections and may I know whether Government is thinking of suitably amending the election law in order to prevent this happening all over the country?

Shri G. S. Pathak: The question related only to U.P. I have not made any enquiry from the Commission with regard to the happenings in other States. So far as the question whether the law will be amended or not, to be more correct whether Government is thinking of amending the law or not, is concerned, I would invite the hon. Member's attention to section 171(c) of the Penal Code which lays down that anyone who interferes with the freedom of the electoral process will be committing an offence which is punishable under the Penal Code.

श्री रामसेवक यादव : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री और उपगृह मन्त्री, जो आगरा से

चुनाव लड़े थे, तथा इनके अलावा उप-शिक्षा मन्त्री जो लखनऊ-उत्तर से इलेक्शन लड़े थे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी सरकारी साधनों के उपयोग का आरोप लगाया था तथा चुनाव में गिनती के लिये भी आरोप लगाये ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जितने आरोप लगाये गये और जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं, उनके मुताल्लिक मैंने आज ही बयान दिया है कि फहरिस्त दे दूंगा, इसमें आप देख लीजिये कि किस किस पर आरोप लगाये गये हैं।

श्री रामसेवक यादव : फहरिस्त यहां रख देंगे, लेकिन बताते क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर उनके पास अलेहदा फहरिस्त न हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। वह फहरिस्त में देख लेंगे कि उनके खिलाफ हैं या नहीं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Since I appreciate the eagerness of the hon. Minister to have an impartial enquiry, may I know whether it falls under the purview of the Government or the Election Commission exclusively to enquire into the matter? If it is under the purview of the Election Commission, does he want to see that the enquiry is made not by the electoral officer because in every State he is a nominee of the State Government rather than somebody else? That is the point which hon. Members would like to know.

Shri G. S. Pathak: So far as the Government is concerned, there is a Government Servants' conduct rule prohibiting interference by the Government servants in the electoral process. I know of the Central rule. I believe that there is a similar rule for the States also. The Government can certainly take action under that rule if Government is convinced that somebody has broken that rule.

Shri Bhagwat Jha Azad: Is that a reply to my question?

Shri G. S. Pathak: I am answering the question, I have not completed it yet.

श्री हुकुम चन्द कछवाय : आप पहले अपने सहायक मन्त्री से पूछ लीजिये, वह कुछ कह रहे हैं।

Shri G. S. Pathak: My hon. friend Shri Azad could have objection if I had sat down, and that might have shown that I had completed the answer. (*Interruptions*).

Shri Bhagwat Jha Azad: You are not answering the question. That is why I am objecting.

Shri G. S. Pathak: I know you are objecting to everything, I know that.

Shri Bhagwat Jha Azad: I object to a lawyer coming in Parliament and behaving in this manner. He ought to behave in a proper way. If you are a Minister it does not matter, you must know how you should behave in Parliament. This is not the Supreme Court. This Minister must know how to behave. How can he cast an aspersion that I am objecting to everything. Why should he do it in that manner?

Mr. Speaker: Would he sit down?

Shri Bhagwat Jha Azad: Yes, I am sitting down, but the Minister should behave better. This is not a law court for earning money.

श्री बागड़ी : सदन से बाहर निकाल दीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर किसी विरोधी की बात होती, तो उसको सजा मिलती। विधि मन्त्री को क्या अधिकार है कि इस तरीके से बात करें। मैं सदन के सामने रखता हूं कि विधि मन्त्री को निकाला जाए।

Shri Bhagwat Jha Azad: He must behave properly.

Shri G. S. Pathak: May, I complete the answer, Sir?

Shri Bhagwat Jha Azad: Why should he cast aspersions like this, Mr. Speaker, I want to know. The Minister must know parliamentary manners.

Mr. Speaker: He has said enough, he must sit down now . . . (*Interruptions*).

Shri Bhagwat Jha Azad: He has come to Parliament only a few months back; I am here for the last 12 years and I know things much better than the hon. Minister.

Mr. Speaker: If I had been allowed, I would have said something but when Members take recourse to their own agitated minds and they give them out and have their own way, what can I do?

Shri Bhagwat Jha Azad: I am sorry.

Mr. Speaker: So many Members have said enough; there is nothing further that I have to say. If the Members want me to take action at any moment, they should leave it to me . . . (*Interruptions*). There ought to be some end.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप एक्शन लेना चाहें तो वह बात सदन के सामने रखी जा सकती है । लेकिन अगर आप एक्शन लेना ही न चाहें तो यह तो कोई कायदे की बात नहीं है । जो गैर-कानूनी बात होती है, गैर-रस्मी बात होती है, चाहे वह किसी की तरफ़ से हो, उसके खिलाफ़ आपको एक्शन लेना चाहिये । चाहे उस बारे में एक्शन लेने के लिये आपका मन हो या न हो । सदन की मर्यादा को रखना है तो आपको ऐसा करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । अगर कोई मेम्बर कसूर करता है और दूसरा उससे ज्यादा कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूं । दूसरे मेम्बरों को यह हक़ है कि वह ऐसे मामले को मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसमें गलती करने वाले को रेप्रिमेंड करूं या कुछ करूं ।

श्री बागड़ी : इसी लिये तो मैंने आपको प्रेस नहीं किया, फरियाद की है, आप इस वक्त मन्त्री को बचा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो मन्त्री को बचा रहा हूं, यह भी ठीक है ।

Shri G. S. Pathak: I further wanted to say that the Election Commission is an independent body. The allegations made against the individuals concerned are before the Election Commission. Government cannot interefere with their working as under article 324 of the Constitution, that is an independent body. So far as Government is concerned, I have placed the position before the House.

Shri Surendranath Dwivedy: The question has not been answered. The simple question was whether the officer to hold the enquiry was a nominee of the State Government, whether the enquiry was conducted by the same officer or not.

Shri G. S. Pathak: I shall place the entire information which I have received from the Election Commission.

Mr. Speaker: The simple question is whether this enquiry has been held by the electoral officer who is a servant of the State Government.

Shri G. S. Pathak: I am not in a position to say whether the electoral officer, who is to make the enquiry under the orders of the Election Commission is a government servant or not. I can enquire (*Interruptions*).

Mr. Speaker: The hon. Members are very well aware that though the Election Commission is an independent body, the machinery that it

uses is always from the State Governments; these electoral officers are servants of the State Governments. There is no doubt about it. Why should there be a question about it? Though there might be some that might be from outside, most of the electoral officers are taken from the State Governments. They are State servants; there is no doubt about it. But then too, our Constitution has provided that it is an independent machinery because it is presided over by the Chief Election Commissioner who is certainly under the Constitution an independent man.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के बारे में जो विधि मन्त्री का घोर अज्ञान है उस पर आप कोई रोक लगायेंगे अथवा नहीं।

Agricultural Credit Corporations

\+

*183. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Warior:
Shri Eswara Reddy:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Dighe:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1595 on the 10th May, 1966 and state:

(a) whether the question of setting up Agricultural Credit Corporations in the States has since been considered by Government; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). The matter is still under consideration.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समय या अवधि की भी कोई सीमा है कि कब तक इस पर सरकार निर्णय ले लेगी।

श्री श्यामधर मिश्र : सरकार अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बतला सकती। जांच हो रही है। ड्राफ्ट बिल बन रहा है। ज्यों ही फाइनेन्स मिनिस्ट्री उसे बना देगी, वह सदन के सामने आयेगा।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सरकार इस के सम्बन्ध में प्रदेश सरकारों से कोई पूछताछ करेगी।

श्री श्यामधर मिश्र : प्रादेशिक सरकारों से पूछताछ की जा चुकी है इस सम्बन्ध में। एक कान्फरेंस हुई थी जिसमें चीफ़ मिनिस्टर्स भी आये थे और मिनिस्टर आफ़ ऐग्रिकल्चर और कोआपरेशन भी थे। उनसे पूरी पूछताछ हो चुकी है।

Shrimati Ramdulari Sinha: May I know whether Government has reseived any protest against setting up of such Agricultural Credit Corporation and, if so, from which States, and may I know whether it is a fact that such Credit Corporation is going to affect the co-operative structure?

Shri Shyam Dhar Misra: No, Sir. As a matter of fact, this attempt will be to strengthen ultimately the co-operative structure, and we have got a unanimous recommendation from all the State Governments for acceptance of this scheme.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी आबादी के ऊपर यह निगम बनाया जायेगा, यह दस हजार कृषियों पर होगा या पांच हजार कृषियों पर होगा।

श्री श्यामधर मिश्र : यह नियम आबादी के ऊपर नहीं बनाया जायेगा। पांच राज्यों में यह निगम बनाया जा रहा है जिनमें असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के इलाके हैं और यह कोआपरेटिव स्ट्रक्चर के जरिये ऋण देगा। यह देखना पड़ेगा कि कहां पर कोआपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत वीक है, उन